

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./124/2016/बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोडेंटगण

1. बाबूराम पुत्र शिवजीराम जाति जाट बनाम 1.वीरमाराम पुत्र पुरखाराम
2. दलाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी मानाणियों की बस्ती (गंगाला) तहसील रामसर, जिला बाड़मेर। 2.रामाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट, निवासी निहालाणियों का टीबा (गंगाला) तहसील रामसर, जिला बाड़मेर।
- 3.छगनदेवी पत्नी सरूपाराम
- 4.गोमाराम पुत्र तगाराम
- 5.आम्वाराम पुत्र तगाराम जाति दर्जी, निवासी मानाणियों की बस्ती (गंगाला) तहसील रामसर जिला बाड़मेर।
- 6.जेठमालसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत, निवासी ढोक तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
- 7.दलाराम पुत्र खरथाराम
- 8.पेमाराम पुत्र खरथाराम
- 9.खूमाराम पुत्र अमराराम जाति जाट, निवासी मानाणियों की बस्ती (गंगाला) तहसील रामसर, जिला बाड़मेर।
- 10.श्रीमान तहसीलदार रामसर, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 05/2015 बअनवान वीरमाराम वगैरा बनाम छगनीदेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.06.2016 के विरुद्ध पेश हुई।




अपीलस्थिति

1. वकील श्री प्रवीण के जाट अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रतनराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री प्रेमराम सोनी रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक:- 14.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरदाता संख्या 01 व 02 एवं अपीलांतगण एवं उत्तरदाता संख्या 2 ला 9 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 286 रकबा 01 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 360/287 रकबा 76. 17 बीघा कुल रकबा 77.07 बीघा व खसरा संख्या 344/271 रकबा 16.04 बीघा,


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बावजूद एकतरफा निर्णय कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई। परन्तु लोक अदालत के नोटिस अपीलांट को नहीं दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई, न ही किसी प्रकार की साक्ष्य ली गई तथा न ही उतरदातागण संख्या 1 व 2 तथा अपीलांट व उतरदातागण संख्या 3 ला 9 का कितना-कितना हिस्सा है, इसके बारे में भी किसी भी प्रकार की न तो मोखिक साक्ष्य ली है तथा न ही दस्तावेजी साक्ष्य ली गई। मात्र उतरदातागण संख्या 1 व 2 की कल्पना एवं वाद पत्र को आधार मानते हुये अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। प्रारम्भिक डिक्री में जमाबंदी के अनुसार हिस्से तय किये जाते हैं। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया। अपीलांटगण द्वारा साफ हाथों से एवं सद्भवना के साथ न्यायालय में अपील पेश नहीं की है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।



सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय उभयपक्ष की अनुपस्थिति में पारित किया गया। सर्वप्रथम दिनांक 17.08.2016 को ज्ञान हुआ तब अपीलांटगण द्वारा आदेश 09 नियम 07 सी पी सी का प्रार्थना-पत्र पेश किया तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले मांगी, जो नकले दिनांक 22.08.2016 को प्राप्त हुई। तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का

राजस्थान अपील प्राधिकारी
— जायपुर

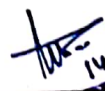
विस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निरतारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर विवाद शुमार की जाती है।


पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर भ्रमन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांत संख्या 01(प्रतिवादी संख्या 05) व अपीलांत संख्या 02 (प्रतिवादी संख्या 08) के सम्मन अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.12.2015 के मुताबिक पर्याप्त तामीलशुदा करार दिये गए हैं जिससे उनके विरुद्ध अनुपस्थिति के फलस्वरूप एकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह भी पाया है कि वाद में उपस्थित उभयपक्ष वाद पत्र को स्वीकार कर प्रतिवादी पक्ष भी अपने प्रतिवादी के अनुरूप विभाजन चाहता है। वादग्रस्त भूमि में हक-हिस्सों के संबंध में कोई विवाद नहीं है लिहाजा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.06.2016 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांतगण इस प्रारंभिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर सकते हैं ताकि उभयपक्ष की विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई की जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जा सके।

अतः अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 05/2015 बअनवान वीरमाराम वगैरा बनाम छगनीदेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.06.2016 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक 1089 दिनांक 17.08.2016 (मौका फर्द दिनांक 11.08.2016) पर उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर निर्णय/अंतिम डिक्री पारित करे।



यह आदेश आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


14/6/19
(नखतदाना औरहठ) बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर


14/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर